सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

# हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-279 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, शुक्रवार 13 जून , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50


# विमान हादसे से हर तरफ मातम, रेलवे बना राहत का मरहम

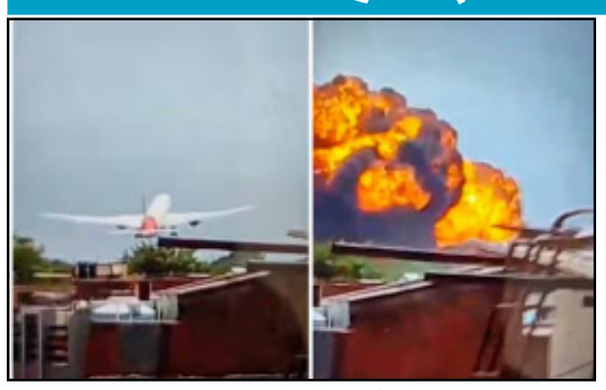

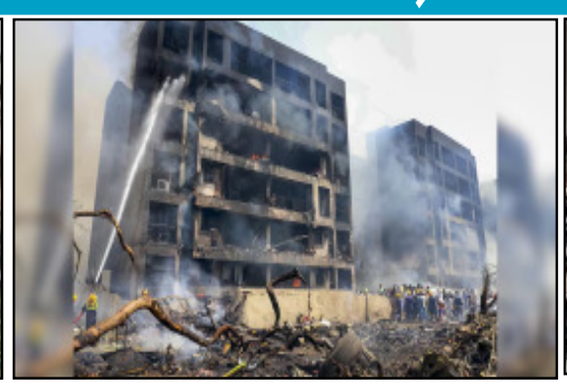

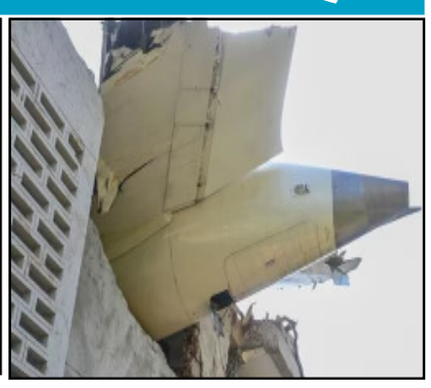

अहमदाबाद। गुजरात की धरती पर एक बार फिर दुख का साया छा गया जब 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। हादसे की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि विमान पूरी तरह ईंधन से भरा था और क्रैश के साथ ही आग का विशाल गोला बन गया।

**धुएं का गुबार, चीख-पुकार और राहत बचाव की दौड़**

विमान का संपर्क कॉल के तुरंत बाद टूट गया और वह मेघाणी नगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटनास्थल पर भीषण आग, धुएं का गुबार और हाहाकार मच गया। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एंबुलेंस की टीमें तैनात की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राम मोहन नायडू को राहत कार्यों के निरीक्षण के लिए भेजा।

विमान दुर्घटना के बाद अहमदाबाद में फंसे सैकड़ों यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने राहत की बड़ी घोषणा की है। वहीं पश्चिम रेलवे दकी ओर से दो स्पेशल सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो अहमदाबाद से दिल्ली और मुंबई के लिए रवाना होंगी।

स्पेशल ट्रेन डिटेल्स-एक नजर

अहमदाबाद-दिल्ली वंदे भारत स्पेशल (09497/09498)

09497- अहमदाबाद से दिल्ली-12 जून, रात 11:45 बजे

09498- दिल्ली से अहमदाबाद -13 जून, शाम 5:30 बजे

रुकानें- महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, अजमेर, जयपुर, अलवर, गुड़गांव

कोच- AC 3-टियर

अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल स्पेशल (09494/09493)

09494-अहमदाबाद से मुंबई - 12 जून, रात 11:55 बजे

09493-मुंबई से अहमदाबाद - 13 जून, सुबह 11.10 बजे

रुकानें-वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, बोरिवली

कोच: AC चेयर कार और AC 3-टियर

बुकिंग IRCTC और सभी PRS काउंटरों पर तत्काल प्रभाव से शुरू हो चुकी है।

**बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू**

बहरहाल ट्रेन संख्या 09497,09494 और 09493 और की बुकिंग तत्काल प्रभाव से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

# एयर इंडिया हादसा-खुशबू पति से मिल नहीं पाई, डॉ. कोमी का पूरा परिवार खत्म

उदयपुर। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के क्रैश होने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है. राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और बालोतरा जिले में भी मातम छाया हुआ है. इस हादसे में उदयपुर जिले के चार लोग, बांसवाड़ा जिले के एक परिवार के पांच सदस्य और बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित की मौत हो गई. इस हादसे में अब तक 204 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि राजस्थान के 10 लोगों की मौत हुई है.

**उदयपुर जिले के चार यात्री थे फ्लाइट में सवार**

मावली तहसील के रोहीड़ा गांव के रहने वाले प्रकाश मेनारिया लंदन में शेफ के तौर पर कार्यरत थे. वहीं, वल्लभनगर तहसील के रूण्डेडा गांव के निवासी लंदन में ही काम करते थे. भारत में छुट्टियां बिताने के बाद वो अहमदाबाद से लंदन लौट रहे थे. उदयपुर से अहमदाबाद की दूसरी 250 किलोमीटर है. उदयपुर संभाग के ज्यादातर लोग अहमदाबाद से ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं.

सगे भाई-बहन की लंदन यात्रा बनी अंतिम सफर

शुभ मोदी (25 वर्ष) और शगुन मोदी (23 वर्ष) उदयपुर शहर के सहेली नगर के निवासी हैं. शुभ ने यूके से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. शगुन ने अहमदाबाद से बीए और बीबीए किया था. दोनों भाई-बहन लंदन में अपने दोस्तों के पास घूमने जा रहे थे. दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों ने अपने पिता संजीव मोदी को कॉल करके फ्लाइट में बैठने की सूचना दी. कुछ मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश हो गई.

**पायल का लंदन में पढ़ने का सपना टूटा**

उदयपुर जिले की गोगुंदा निवासी पायल खटीक की भी मौत हो गई है. यह उदयपुर से इस हादसे में पांचवीं मौत की पुष्टि है. पायल लंदन पढ़ाई के लिए जा रही थी और एडमिशन लेने जा रही थी. वह अपने परिवार के साथ गुजरात के हिम्मतनगर में रहती थी.

**बांसवाड़ा का एक पूरा परिवार भी हादसे की चपेट में**

डॉ. प्रतीक जोशी मूल रूप से बांसवाड़ा के निवासी हैं, जो छह साल पहले लंदन शिफ्ट हो चुके थे. प्रतीक अपनी पत्नी डॉ. कोमी जोशी और तीन मासूम बच्चों को स्थायी रूप से लंदन ले जाने के लिए इस फ्लाइट में सवार हुए थे. डॉ. कोमी ने दो दिन पहले ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था.

**खुशबू राजपुरोहित अपने पति से नहीं मिल पाई**

बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित की इसी साल जनवरी में उनकी शादी विपुल से हुई थी. विपुल लंदन में डॉक्टर हैं. वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेज पूरे होने के बाद खुशबू पहली बार पति से मिलने के लिए लंदन रवाना हो रही थी. उन्हें उनके पिता मदन सिंह अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़ने भी गए थे।

**परिजन पहुंचे अहमदाबाद**

फ्लाइट क्रैश की खबर के बाद उदयपुर और बांसवाड़ा के सभी पीड़ितों के परिजन तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए. उदयपुर के सहेली नगर में शुभ और शगुन मोदी के घर पर मातम पसरा है।

# लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान खतरे में है-गहलोत

उदयपुर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज गुरुवार 12 जून को 3 दिनी उदयपुर संभाग के दौरे पर उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों ने अशोक गहलोत पर कई सवाल पूछे। अशोक गहलोत ने कहा पूरा देश देख रहा है। ऐसा तनाव मुल्क के अंदर आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा ध्रुवीकरण। यह देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, यह मेरा मानना है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग साथ चलें तभी लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।

**चुनाव जीतना एक बात है मगर लोकतंत्र बचाना दूसरी बात**

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा चुनाव जीतना एक बात है मगर लोकतंत्र बचाना दूसरी बात है। धीरे-धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान खतरे में है। अशोक गहलोत ने कहा राहुल गांधी बार-बार बोल रहे हैं संविधान बचाओ, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या मंशा है। जिस प्रकार हर क्षेत्र में ज्यूडिशियरी में सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा है।

**लोकपाल को लेकर हमारी सरकार बदल गई पर क्या हुआ**

अशोक गहलोत ने कहा कि क्या आपने सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) का नाम सुना है। एक जमाने सीवीसी का देश में भय था। आज यह हाल है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसका नाम ही कोई नहीं जानता है। लोकपाल को लेकर हमारी सरकार बदल गई। लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के धरने हुए। यह पूरी तरह से आरएसएस से स्पॉन्सर था। 2 जी स्पेक्ट्रम, कोलगेट जैसे घोटलों को लेकर देश में माहौल बना दिया गया था। अब हम सवाल करते हैं कि 11 साल बीत चुके जो आरोप लगे थे उस पर सरकार ने क्या किया। जवाब दे।

**सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए-अशोक गहलोत**

अशोक गहलोत ने कहा लोकतंत्र में विपक्ष का एक महत्व होता है। बिना विपक्ष के पक्ष नहीं होता है। विपक्ष जनता के लिए आवाज उठाता है। सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। राहुल गांधी ने आवाज उठाई। उन्होंने पहलगाम की हत्या के बाद के जब सत्ता पक्ष सवाल पूछे गए तो सरकार कोई जवाब नहीं दे सकी। मारने वालों का क्या हुआ, सरकार को कुछ पता नही। अशोक गहलोत ने कहा फिर सिंदूर हो गया। सवाल उठाए गए। पर कोई जवाब नही। राहुल गांधी ने कहा पूरा विपक्ष के मोदी के साथ है। पहली बार पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा था। सेना के साथ खड़ा हुआ। पर उसका फायदा मिलना चाहिए था। पर कुछ नहीं।

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मानवीय पहल

# अब अज्ञात, बेसहारा और अनाथ रोगियों को मिल सकेगा निःशुल्क इलाज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मानवीय पहल एवं मार्गदर्शन में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने असहाय, वंचित, मानसिक रूप से अक्षम, लावारिस और अज्ञात रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संवेदनशील कदम उठाया है। अब इन रोगियों को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक संयुक्त एमओयू किया गया है। इसके तहत रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट या एनजीओ के माध्यम से चिकित्सालयों में लाए जाने वाले रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।

**इसलिए नहीं मिल पाता था योजनाओं का लाभ-**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि प्रायः यह देखने में आता था कि रेलवे

स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर असहाय, मानसिक रूप से अक्षम, लावारिस या अज्ञात रोगी बेसहारा स्थिति में पाए जाते थे और ऐसे व्यक्तियों को धर्मार्थ ट्रस्ट या एनजीओ द्वारा चिकित्सालयों में लाया जाता था, लेकिन पहचान पत्र (आधार/जन आधार/अन्य) के अभाव में उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या अन्य योजनाओं में निःशुल्क इलाज, ऑपरेशन या इंप्लांट लगाया जाना संभव नहीं हो पाता था। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए राजस्थान का निवासी होना एवं कोई पहचान पत्र होना आवश्यक है। ऐसे लोगों की पहचान या पता नहीं होने अथवा राजस्थान के निवासी होने का पहचान पत्र नहीं होने के कारण उपचार नहीं मिल पाता था।

**मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूं निकली जीवन रक्षा की राह**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ऐसे रोगियों के समुचित उपचार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड ट्रस्ट या एनजीओ द्वारा लाए गए रोगियों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे ट्रस्ट या एनजीओ को केवल यह प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि लाया गया रोगी असहाय, वंचित, लावारिस या अज्ञात है। यह प्रमाण पत्र निःशुल्क इलाज के लिए पर्याप्त होगा। चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जो ट्रस्ट/एनजीओ को अधिकृत करेगी और एमओयू के आधार पर सहयोग सुनिश्चित करेगी। योजना के तहत होने वाला व्यय आरएमआरएस के माध्यम से वहन किया जाएगा।

**मानवता की दिशा में बड़ा कदम**

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रदेशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं। अब इस एमओयू से इन निःशुल्क सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालड्डों, विधवा/अनाथ / लावारिस व्यक्तियों, दुर्घटनाग्रस्त रोगियों और 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को इससे उपचार लेने में और सुगमता होगी। जरूरतमंद एवं बेसहारा रोगियों को आसानी से उपचार उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान सरकार का यह कदम मानवता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

## आवासन मंडल ने नई आवास योजनाओं के लिए आवेदन की बढ़ाई अंतिम तिथि, अब 26 जून तक कर सकेंगे आवेदन

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल ने आमजन की उत्साहजनक भागीदारी को देखते हुए नवीन आवासीय योजनाओं की अंतिम आवेदन तिथि को 26 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय उन आवासीय योजनाओं के लिए लिया गया है जो विभिन्न आय वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं।

**तीन जिलों की योजनाओं में तिथि वृद्धि**

आवास मंडल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, धौलपुर, बूंदी, और बारां जिलों की आवासीय योजनाओं में आवेदन तिथि बढ़ाई गई है

धौलपुर-सेक्टर-5 में 1 स्वतंत्र आवास

बूंदी-लाखेरी आवासीय योजना में कुल 6 स्वतंत्र आवास

बारां - गजनपुरा आवासीय योजना में कुल 9 स्वतंत्र आवास

अब इन योजनाओं में इच्छुक आवेदक 26 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

**जयपुर की योजनाओं में जबरदस्त प्रतिक्रिया**

आवासन मंडल की जयपुर स्थित योजनाओं में लोगों से अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला है। आंकड़े इस प्रकार हैं-

गंगा अपार्टमेंट फेज-2, प्रताप नगर - 80 फ्लैट्स के लिए कुल 287 आवेदन प्राप्त हुए । यानी तीन गुना से अधिक।

गुलमोहर योजना, मानसरोवर -160 फ्लैट्स के लिए 329 आवेदन प्राप्त हुए ड्ड यानी दो गुना से अधिक।

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि आवासन मंडल की योजनाओं को लेकर आमजन में भारी भरोसा और रुचि बनी हुई है।

सुविधाजनक पंजीकरण प्रक्रिया-राजस्थान आवासन मंडल ने पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया है, जिससे आवेदक घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। यह पहल विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक सुलभ गृह स्वप्न को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

## ललित मोदी की पारिवारिक कंपनी के गोदाम पर छापा

# कृषि मंत्री ने किया खुलासा, नकली पेस्टिसाइड जब्त

जयपुर। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार देर शाम छापेमारी कर पेस्टिसाइड उत्पादक कंपनियों की पोल खोल दी। मंत्री मीणा ने आरोप लगाया कि कई प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर नकली और अमानक स्तर के कीटनाशकों का भंडारण और बिक्री हो रही थी, जिससे किसानों की लाखों बीघा फसलें बर्बाद हो गईं।

**इंडोफिल के गोदाम सील, ललित मोदी का नाम आया सामने**

छापेमारी के दौरान जयपुर के महादेव नगर और चौमूं इलाके में स्थित इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड का गोदाम सील किया गया। मंत्री ने दावा किया कि यह कंपनी

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के परिवार से जुड़ी है। कंपनी में रुचिर मोदी, चारू मोदी और पारुल मोदी बतौर डायरेक्टर दर्ज हैं।

**किसानों ने सफेद मक्खी से बचाव के लिए इस कंपनी का पेस्टिसाइड 10,000 रुपये प्रति किलो तक खरीदा। इसके बावजूद कपास की फसल बर्बाद हो गई।**

यह गंभीर मामला है, – कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा

**नकली कीटनाशक और अवैध गोदाम**

राज्य सरकार की टीम ने इंडोफिल समेत 6 कंपनियों की जांच की जिनमें श्रीराम कृषि रसायन लिमिटेड, उदित ओवरसीज लिमिटेड और अन्य शामिल थीं।

जांच में सामने आया कि-

कई गोदाम बिना अनुमति के चल रहे थे।

उत्पाद नकली थे या गुणवत्ता मानकों से नीचे।

फर्जी लेबलिंग कर प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम पर पेस्टिसाइड बेचे जा रहे थे।

**कड़ी कार्रवाई के आदेश**

डॉ. मीणा ने कहा कि पेस्टिसाइड रूल्स 1968 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही शुरू की जा रही है।

नकली उत्पादों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई गई है और कई गोदामों को सील कर दिया गया है। साथ ही दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।

कृषि मंत्री पिछले 15 दिनों से नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी बड़े स्तर पर छापे मारे गए हैं। इस मुहिम से जहां किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं व्यापारिक संगठनों में नाराजगी भी देखी जा रही है।

# भारत की सुरक्षा एवं मोदी सरकार

11 वर्ष के सफलतम कालखंड में केवल विदेशों से शस्त्र खरीद ही नहीं हमने स्वयं के आत्मनिर्भर होने के मंत्र को भी पहचाना है। अब हम भारत में उन्नत एवं आधुनिक स्वदेशी शस्त्रों का निर्माण भी कर रहे हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रुस्तम यूएवी ड्रोनसका डीआरडीओ द्वारा लखनऊ में निर्माण, रूस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल,टाटा -डसाल्ट के साथ राफेल के मुख्य भाग का हैदराबाद में हम निर्माण करने वाले हैं।

(लेखक - शिवप्रकाश)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही है। संपूर्ण देश में मोदी सरकार की सफलता पर प्रेस वार्ताएं, प्रदर्शनी, विचार संगोष्ठी, जनसभाएं एवं ग्राम स्तर पर चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सोशल मीडिया द्वारा योजनाओं की जानकारी एवं अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो रहा है। गरीब कल्याण, ढांचागत विकास,अन्तर्वाह्य सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक उत्थान एवं विदेशों में बढ़ता भारतीय सम्मान सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां 11 वर्ष में प्रगति की गवाह है. भारत सहित विश्व की अनेक संस्थाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने इस ऐतिहासिक सफलता की प्रशंसा की है। रक्षा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की उपलब्धियां ऐतिहासिक है।

चाणक्यनीति में कहा कि 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते' शास्त्रों की चर्चा भी तभी संभव है जब राष्ट्र सभी प्रकार से सुरक्षित हो। सिद्धांत कितना भी श्रेष्ठ हो उसकी सफलता उस सिद्धांत का अनुसरण करने वालों की शक्ति पर ही निर्भर करती है। इसी कारण विद्वानों ने शक्ति को ही शांति का आधार बताया है7 राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो इस सिद्धांत को ही प्रतिपादित करते हैं।

भारतीय जनसंघ ने अपने 1964के पटना अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करते हुए मांग की थी कि भारत को परमाणु बम बनाने के सभी प्रयत्न करने चाहिएँ। 'सिद्धांत एवं नीतियां' नामक दस्तावेज में भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने की बात की थी। प्रस्ताव प्रतिपादन करते समय कहा गया था कि हमारे आराध्य सभी देवी-देवता धर्म संस्थापना के लिये शस्त्रधारी है। इसलिए भारत माता भीपरमाणु बम धारी होनी चाहिए। इसी नीति का अनुसरण करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1999 में पोखरण परमाणु विस्फोट कर विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया था7 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद देश अपने हितों की सुरक्षा करने में समर्थ बने इस प्रकार की नीति पर चला।आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीतिइसी का उदाहरण है7 जहाँ कांग्रेस सरकार में आतंकियों के लिए जी जैसे सम्मानपूर्वक शब्दों का उपयोग एवं बिरयानी खिलाना जैसे उपक्रम चल रहे थे वहीं मोदी सरकार में सेना और सुरक्षा बलों को आतंक से लड़ने के लिए छूट एवं सुरक्षा बलों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये गए।

रक्षा क्षेत्र का बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ था अब 2025-26 के लिए वह बढ़कर 6.81 लाख करोड़ अर्थात तीन गुना से अधिक हो गया है। 2015 कैग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के पास केवल 20 दिन का गोलाबारूद उपलब्ध था। व्यक्तिगत सैनिक स्तर पर, सैनिकों को अब स्वदेशी रूप से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली बुलेटप्रूफ जैकेट, उन्नत हेलमेट, नई बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म, नाइट विजन डिवाइस और थर्मल इमेजर उपलब्ध करायी गई। मोदी सरकार के आने के बाद सेना के समन्वय के लिएलंबित मांग सीडीएस की नियुक्ति का निर्णय हुआ। ऑपरेशन सिन्दूर में तीनों सेनाओं के समन्वय में हमने इस निर्णय की भूमिका को अनुभव किया है। शस्त्रोंकी खरीद के लंबे समय से लंबित निर्णयों का भी शीघ्र निस्तारण होते हुए हम देख चुकेहैं। फ्रांस से आने वाले राफेल की खरीद इसी प्रक्रिया का परिणाम है।एस -400 , सुखोई - 30, इजराईल से ड्रोन, हैमर मिसाईल, चिनूक हेलिकॉप्टर, एलसीएच प्रचंड (लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर), तेजस फाइटर जेट (पूर्ण स्वदेशी विमान), पिनाका राकेट सिस्टम, वरुणास्त्र आदि की उपलब्धता के कारण भारतीय सेना विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में गिनी जाती है। ऑपरेशन सिन्दूर में निर्धारित लक्ष्य पर मार एवं शत्रु के ड्रोन एवं मिसाईल को मार गिराने में हम सक्षम हुए है।

11 वर्ष के सफलतम कालखंड में केवल विदेशों से शस्त्र खरीद ही नहीं हमने स्वयं के आत्मनिर्भर होने के मंत्र को भी पहचाना है। अब हम भारत में उन्नत एवं आधुनिक स्वदेशी शस्त्रों का निर्माण भी कर रहे हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रुस्तम यूएवी ड्रोनसका डीआरडीओ द्वारा लखनऊ में निर्माण, रूस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल,टाटा - डसाल्ट के साथ राफेल के मुख्य भाग का हैदराबाद में हम निर्माण करने वाले हैं। रक्षा उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 174 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46529 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 127265करोड़ हुआ है7



रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी - 17 नवंबर 2021 ('राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व', झांसी में) के अपने संबोधन में कहाँ कि -

'भारत अपनी रणनीतिक व सुरक्षा आवश्यकताएँ अन्य देशों पर निर्भर होकर पूरा नहीं कर सकता ... सरकार निरंतर 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में प्रयासरत है।'

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति के कारण अब हम खरीदने अर्थात आयात करने वाले देश नहीं हम बेचने वाले अर्थात निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। 2004 से 2014 अर्थात 10 वर्षों में हमने 4312 करोड़ का निर्यात किया था। 2014 से 24 में 88,319 करोड़ का हुआ है। 2024 - 25 में केवल एक वर्ष में ही हमने 23622 करोड़ का निर्यात किया है। आयात में 21न की कमी करके 11 वर्षों में निर्यात में 34 प्रतिशत की वृद्धि करने में देर सक्षम हुआ है. आज हम लगभग 80 से अधिक देशों में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे स्वदेशी शस्त्रों की सफलता को देखकर विश्व में हमारे शस्त्रों की मांग भी बढ़ गयी है।

देश को नक्सल मुक्त करने के मोदी सरकार के संकल्प ने देश के सामान्य नागरिको में सरकार के प्रति विश्वास जगाया है। नक्सली हिंसा में लिप्त आतंकी अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं। 2014 में नक्सल आतंकवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। 11 वर्षों बाद 2025 में वह संख्या मात्र 6 रह गई है। बड़े-बड़े इनामी नक्सली आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं। सरकार के नक्सलमुक्त देश के संकल्प से लगता है कि भावी पीढ़ी नक्सलवाद नाम ही भूल जाएगी.

प्रत्येक प्रकार की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया, जिसमें औपनिवेशिक सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित अष्टकोणीय प्रतीक को स्थान दिया गया।इसमें अशोक स्तंभ, लंगर और नौसेना का आदर्श वाक्य 'शं नो वरुण:'अंकित है, जो भारत की समुद्री विरासत और आत्मगौरव का प्रतीक है।नए भारत का संकल्प- घर में घुसकर आतंकियों को मारेंगे केवल कहना मात्र नही, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर में हमने यह करके दिखाया है। खून एवं पानी एक साथ नहीं बहेगा सिंधु नदी समझौता रद्द कर हमने आतंक के प्रति अपने दृष्टिकोण को विश्व के सामने स्पष्ट किया है। पूर्व सैनिको के कल्याण, अग्नि वीर योजना,विजयदशमी पर राफेल जैसे शस्त्रों का पूजन एवं दीपावली त्योहार में सैनिको के मध्य प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, सीमावर्ती सैनिक चौकियों पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जी का प्रवास यह सभी उपक्रम हमारे सुरक्षित भारत के संकल्प को प्रकट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने, आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण को विश्व के सम्मुख रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल देश की एकजुटता को प्रकट करने का कूटनीतिक सराहनीय प्रयास है।

भारत को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यह प्रयास देश की जनता में यह विश्वास जगाने में सफल हुए हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है।

(लेखक- भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

## गर्मी से मुकाबला

ऐसे वक्त में जब भारत के अनेक हिस्सों में तेज गर्मी से पारा उछल रहा है, तपिश से बचने के लिये बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि स्वाभाविक बात है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक गर्मी की तपिश से बचने के लिये कूलर से लेकर एसी तक का भरपूर इस्तेमाल करता है। हाल के दिनों में घरों, कार्यालयों, होटलों व मॉल तक में एसी का उपयोग बेतहाशा बढ़ा है। जिसके चलते गर्मियों के पीक सीजन में बिजली की खपत चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे वक्त में केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर यानी एसी की पहचान बिजली की बढ़ती खपत के लिये जिम्मेदार खलनायक के रूप में की है। केंद्र सरकार योजना बना रही है कि घरों,होटलों व कार्यालयों में बीस डिग्री से अट्ठाइस डिग्री सेल्सियस के बीच इस्तेमाल होने वाले इस उपकरण की कूलिंग रेंज को मानकीकृत किया जाए। नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद एसी निर्माताओं को बीस डिग्री से कम तापमान पर कूलिंग प्रदान करने वाले एसी बनाने से रोक दिया जाएगा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार केंद्र सरकार की यह पहल बिजली बचाने और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस बात में दो राय नहीं कि गर्मियों की तपिश से बचने के लिये लोग अपने एसी को बहुत कम तापमान पर चलाते हैं। इस प्रवृत्ति का बिजली ग्रिड पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। निश्चित रूप से इसके चलते बिजली कटौती की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इस संकट का अकेला मुख्य समाधान एसी को बेहद कम तापमान पर चलाया जाना ही नहीं है। इसके अलावा अन्य कारक भी हैं। यह भी एक हकीकत है कि सरकारी व निजी कार्यालयों में एसी का उपयोग काफी लंबे समय तक अंधाधुंध ढंग से किया जाता है। यहां इसके उपयोग में किफायत बरतने की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। निस्संदेह, ऊर्जा मंत्रालय का ऊर्जा नियामक ब्यूरो, बिजली खपत कम करने वाले उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देता है। लेकिन जब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती बढ़ रही है तो तापमान बढ़ने पर बिजली की खपत अनिवार्य रूप से बढ़ने लगती है। लेकिन इसका एकमात्र कारण एसी का बढ़ता उपयोग ही नहीं है। हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि हमारे शहर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? हम इस बढ़ते तापमान से नागरिकों को राहत क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अंधाधुंध-अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण कार्य भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। हमने चारों तरफ कंक्रीट के जंगल तो बना दिए लेकिन शहरों में हरियाली का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। जिससे हवा का प्राकृतिक प्रवाह भी बाधित हो रहा है। विकास के नाम पर जो सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ काटे जाते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति नये पेड़ लगाकर नहीं की जाती है। हम घरों को प्राकृतिक रूप से ठंडा बनाये रखने वाली भवन निर्माण तकनीक नहीं अपना रहे हैं। यदि उष्मारोधी भवन निर्माण सामग्री को बढ़ावा दिया जाए तो लोगों को कम बिजली खपत से भी राहत मिल सकती है। हमारी जीवनशैली बिजली की खपत को लगातार बढ़ा रही है। यदि हमारे देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए तो सड़कों पर निजी वाहनों का उपयोग कम होने से वाहनों के गर्मी बढ़ाने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। हमें भवन निर्माण में छतों को ठंडा रखने वाली तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी सामग्री या सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए जो पारंपरिक छत की तुलना में ताप बढ़ाने वाली सूरज की रोशनी को परावर्तित कर सके। इन उपायों से हम ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करने का प्रयास कर सकते हैं।

# धर्म के आवरण में दरिंदिगीः कुछ तो गड़बड़ है

(लेखिका - निर्मल रानी/ईएमएस)

हमारे देश में जितना अधिक धर्म का ढिंढोरा पीटा जा रहा है अधर्म भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ख़ासतौर से जब से आसाराम,स्वामी चिन्मयानंद,गुरमीत राम रहीम,स्वामी नित्यानंद,दाती महाराज,रामपाल,आसाराम के कुपुत्र नारायण साईं,भीमानंद महाराज उर्फ़ शिवमूरत द्विवेदी,राम शंकर तिवारी उर्फ़ स्वामी परमानंद व आशु भाई महाराज जैसे स्वयंभू संतों व डेरा संचालकों से जुड़े मामले सामने आये व इनमें से कई को बलात्कार व यौन शोषण के मामले में जेल जाना पड़ा तब से तो धर्म क्षेत्र में इसतरह के कुकर्मों की गोया झड़ी सी लग गयी। देश में न जाने कितने साधु वेश धारी मंदिर के पुजारी या किसी न किसी रूप में धर्म क्षेत्र से जुड़े लोग यौन हिंसा के शर्मनाक मामलों में पकड़े जा चुके हैं।

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दीपक वर्मा नामक एक बलात्कारी को थाना आलमबाग़ के अंतर्गत पुलिस ने सूर्योदय से पूर्व ही सुबह सवेरे मुठभेड़ में मार गिराया ,यह व्यक्ति भी धर्म का चोला ओढ़े रहता था। स्वयं को माता का भक्त प्रदर्शित करने वाला यह कुकर्मी माता रानी के जागरण समारोहों में झांकियां सजाने व झांकियां निकालने का काम किया करता था। इस ने चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे से ढाई-तीन साल की बच्ची को, जो अपने पिता के साथ लेटी हुई थी,चुपके से उसका अपहरण कर उसे उठा लगाया। बाद में इस व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ दुष्कर्म किया था। मासूम बच्ची अभी भी गंभीर अवस्था में इलाज करा रही है। पुलिस ने माता भक्त इस आरोपी पर एक लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और गत वीरवार को देर रात थाना आलमबाग क्षेत्र के मवैया के निकट एनकाउंटर में ढेर कर दिया।

भारत जैसे धर्म प्रधान देश में में यौन शोषण के मामलों का तेज़ी से बढ़ना अत्यंत चिंता का विषय है। हालाँकि देश में यौन शोषण को लेकर काफ़ी कड़े क़ानून भी बने हुये हैं फिर भी यह एक प्रमुख सामाजिक समस्या बनी हुई है। ख़ासकर धर्म क्षेत्र में कुकर्मियों व अधर्मियों का प्रवेश कर जाना धार्मिक सीख व शिक्षाओं पर भी सवाल खड़े करता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रत्येक 22 मिनट में एक बलात्कार का मामला दर्ज होता है। इसमें वह मामले शामिल नहीं हैं जो भयवश या लाज वाश अथवा सुलह सफ़ाई के बाद या फिर सामाजिक कलंक या कमज़ोर क़ानूनी व्यवस्था के कारण दर्ज नहीं होते और वह सरकारी रिकार्ड में नहीं आ पाते। अन्यथा यह आंकड़े और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। वैसे तो दक्षिण अफ़्रीक़ा,स्वीडन,संयुक्त राज्य अमेरिका,इंग्लैंड,मिस्र,फ़्रांस व इथियोपिया जैसे देश भी महिला शोषण व बलात्कार जैसे मामलों में बदनाम देशों की सूची में शामिल हैं। परन्तु इनमें से कोई भी देश धर्म का उस स्तर पर ढिंढोरा नहीं पीटता जितना भारत में देखने को मिलता है। स्वयं को धर्म प्रधान प्रदर्शित करने वाले भारत जैसे देश में बेशक यह एक अत्यंत गंभीर व संवेदनशील मुद्दा है।

कहीं आश्रमों,मंदिरों व चर्चों में यौन शोषण के मामले सामने आते हैं जहाँ महंत, पुजारी,पादरी जैसे धर्म के आवरण में छुपे लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगता है। जैसे कुछ समय पूर्व कानपुर में एक पीड़िता को पहले नशीला लड्डू खिलाया गया फिर उसका यौन शोषण कर घटना का वीडियो बनाकर उसे धमकाया गया। चार महीने बाद गोविंद नगर थाने में शिकायत तो दर्ज ज़रूर हुई, लेकिन परन्तु चूँकि महंत, पुजारी, और अन्य रेपिस्ट प्रभावशाली थे इस कारण उनके विरुद्ध पुलिस ने देर से कार्रवाई की। इसी तरह मई 2025 में आगरा के एक मंदिर में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना चर्चा में रही। इस मामले में पुलिस ने शुरू में आरोपी को छोड़ दिया था लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उसे फिर से गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह अप्रैल 2025 में सीतापुर में एक मंदिर के पुजारी पर नाबालिग़ लड़की के साथ दुष्कर्म करने और एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगा था। ऐसे ही सतना के नादन थाना क्षेत्र में एक कथा वाचक नारायण स्वरूप त्रिपाठी ने तीन नाबालिग़ बहनों को काल सर्प दोष की पूजा करने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर उनका बलात्कार किया। पीड़िता बहनों के परिजनों की शिकायत पर नादन थाना पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया। इसी तरह कुछ समय पूर्व दिल्ली के द्वारका में बाबा मसानी नामक एक राक्षस को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। इसने पहले तो एक महिला से पांच लाख रूपये मांगे। बाद में पैसे न मिलने से खिन्न इस दुष्ट ने उस महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उससे बलात्कार किया। यह बाबा माता मसानी चौकी के नाम से अपना दरबार चलाता है। यह यू ट्यूबर भी है। ऐसे ही केरल में कैथोलिक चर्च से जुड़े यौन शोषण के मामले चर्चा में रहे। एक नन ने जालंधर के रोमन कैथोलिक चर्च के बिशप पर 14 बार यौन शोषण का आरोप लगाया था । 2019 में तो पोप फ्रांसिस ने भी स्वीकार किया था कि भारत, लैटिन अमेरिका, इटली, और अफ्रीका में बिशप और प्रीस्ट द्वारा ननों का यौन शोषण हुआ है। पटना में 2017 में एक पादरी पर दो महिलाओं के साथ बलात्कार और धर्म परिवर्तन के नाम पर यौन शोषण का आरोप लगा। इसी प्रकार दिसंबर 2024 में संभल, उत्तर प्रदेश, में एक मस्जिद के मौलाना साजिद और उसके भाई पर 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश और तीन घंटे तक बंधक बनाने का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार किया। एक तथ्य यह भी है कि धार्मिक संस्थानों में यौन शोषण के मामलों को अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है। इसकी वजह यह है कि एक तो धार्मिक संस्थान समाज में सम्मानित स्थान माने जाते हैं। दूसरे यह कि वोट बैंक के चलते इनके राजनैतिक रुसूख़ भी होते हैं। यही वजह है कि ऐसे कई मामलों में, प्रभावशाली व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में देरी होती है। जैसे कि आगरा और कानपुर की घटनाओं में पुलिस की प्रारंभिक निष्क्रियता की काफ़ी आलोचना हुई थी । धर्मस्थानों में होने वाली व धर्मिकता का लिबादा ओढ़े लोगों द्वारा ऐसे घटनाओं को अंजाम देने की प्रवृति ने धार्मिक सोच धार्मिक शिक्षा व धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिये हैं।

(चिंतन-मनन)

# कर्म से बना है वर्ण

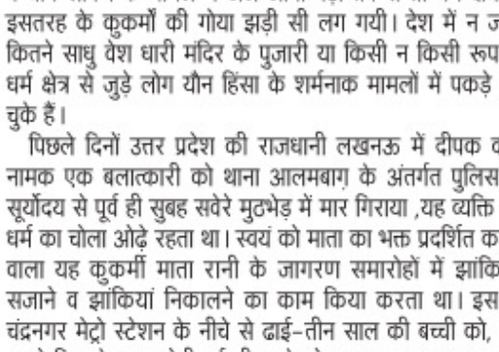




मेरे द्वारा चार वर्णों की रचना गुण और कर्मों के हिसाब से की जाती है, फिर भी तू मुझे कभी न खत्म होना वाला और कर्मों के बंधन से मुक्ति ही जान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं, अब ऐसा मान लेते हैं कि जो जिस घर में जन्म लेता है, वह उसी वर्ण का कहलाता है।

जबकि वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर शुरू हुई थी। पहले जब बच्चे को पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, तब तक वह किसी वर्ण का नहीं कहलाता था। वहां गुरु अपने शिष्यों की रुचि को जानकर उसके हिसाब से उन्हें पढ़ाते थे।

वेदों को पढ़ने में रुचि लेने वालों को ब्राह्मण, युद्ध कला में महारथी को क्षत्रिय, व्यापार में रुचि वाले को वैश्य और सेवा भाव वाले को शूद्र की उपाधि दी जाती थी।

इसके बाद वे समाज में उसी के हिसाब से काम करते थे। यही भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर चार वर्णों की रचना की हैं, जिससे सभी मनुष्य कर्मों में लगे रहें। ये सब करते हुए भी तुम मुझे कभी न खत्म होने वाला और कुछ न करने वाला जानो। सब कुछ करते हुए भी भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता।

विचार मंथन

# अकूत खनिज संपदा के बाद भी अफ्रीकी देश सबसे गरीब?

(लेखक- सनत जैन )

अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के युवा सैन्य नेता इब्राहिम त्रारे ने एक ऐसा भाषण दिया है। जिसमे वैश्विक मीडिया और औपनिवेशिक सोच पर तीखा हमला किया गया है। 34 वर्षीय त्रारे ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है, उन्होंने अफ्रीका की गरीबी, संघर्ष और पिछड़ेपन की झूठी तस्वीर दुनिया के देशों में सालों तक प्रचारित की हैं।

उन्होंने कहा कि अफ्रीका कोई भिखारी महाद्वीप नहीं है, बल्कि दुनिया को दुर्लभ खनिज, ऊर्जा संसाधनों को उपलब्ध कराने वाला विशाल आफ्रिकी महाद्वीप है। अफ्रीका सारी दुनिया को पोषित और विकसित करने वाला महाद्वीप है। सारी दुनिया अफ्रीका के खनिज संसाधनों का दोहन और उपयोग करती है। इसके बदले बड़े-बड़े पूंजीवादी देश अफ्रीका को गरीबी, भ्रष्टाचार और अशांति की ओर ले जाते हैं। त्रारे ने कहा अफ्रीका को मस्जिद नहीं, स्कूल चाहिये। उल्लेखनीय है अफ्रीका की 65 फीसदी मुस्लिम धर्म को मानती है।

अफ्रीका को अब धार्मिक कट्टरता नहीं, शिक्षा और विकास चाहिए है। 200 मस्जिदे बनाए जाने के सऊदी अरब के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसी ताकतों की उन शोषण की रणनीतियों को उजागर किया।जिनसे अफ्रीका को आर्थिक रूप से लूटा जा रहा है। उन्होंने कोबाल्ट, प्लेटिनम, सोना, यूरेनियम जैसे खनिजों के उत्पादन में अफ्रीका के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा, जिन क्षेत्रों से यह बहुमूल्य संपदा निकली जा रही है, उन क्षेत्रों में आज भी बिजली, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। उन स्थानों पर सबसे ज्यादा बदहाली और भुखमरी देखने को मिलती है। त्रारे के यह तेवर केवल एक क्रांतिकारी नेता की आवाज नहीं, बल्कि उस पूरे महाद्वीप की पीड़ा है।

जिसे दशकों से जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर और पश्चिमी देशों ने अपने ऊपर निर्भर बनाकर रखा है। उनका कहना है कि पश्चिमी मीडिया अफ्रीका की सफलताओं और वास्तिवक्ता को कवर नहीं करता। पश्चिमी देशों और पूंजीपतियों के इशारे पर शोषणकारी एजेंडा मीडिया चलाता है। अब इसको बेनकाब करने का समय आ गया है। इब्राहिम त्रारे की यह गर्जना सिर्फ अफ्रीका नहीं, पूरे ग्लोबल साउथ के लिए चेतावनी के रूप में है।

त्रारे के यह तेवर उपनिवेशवाद के नए रूपों, मीडिया के दोहरे मानदंडों और वैश्विक आर्थिक अन्याय के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत है। पश्चिमी देशों की इस लूट में अब चीन भी शामिल हो गया है। सबसे बहुमूल्य खनिज संपदा अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ मिलकर अफ्रीका महाद्वीप की जनता का जो शोषण कई दशकों से स्थानीय नेताओं की मदद से हो रहा है। उसके खिलाफ इसे एक बगावत के रूप में देखा जा रहा है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो सैन्य अधिकारी है। उनकी यह बगावत ठीक वैसी ही है, जैसी महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था।

वही बिगुल अब त्रारे ने अफ्रीकी महाद्वीप में बजा दिया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहायता को ठुकराते हुए यहां तक कह दिया है। जब हम दुनिया की सबसे महंगी खनिज संपदा सारी दुनिया के देशों को देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी बहुमूल्य संपदा का भुगतान चाहिए, वैश्विक कर्ज और दया की हमें आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से अफ्रीका की जनता ने अब अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया है। अफ्रीकी देशों के नेताओं के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ भी वहां की जनता ने एक जंग शुरू कर दी है।

सारी दुनिया में इसे पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एक नई लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। भविष्य में इसका व्यापक असर पड़ना तय है। इस लड़ाई में भारत की सहभागिता महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के कारण अफ्रीकी देशों की जनता में भारत के प्रति बेहतर छबि है। इसका लाभ उठाने भारत को आगे आना होगा।

# भारत में ग्रीन हाइड्रोजन होगा 40 प्रतिशत सस्ता

**नई दिल्ली, एजेंसी।** एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत में आने वाले समय में बड़ी गिरावट हो सकती है। भारत ने 2030 के अंत तक 5 मिलियन टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत में 40 प्रतिशत तक गिरावट आने की संभावना है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े लक्ष्य रखने वाले भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत कम हो सकती है। यह गिरावट सरकार के समर्थन से होगा। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की औसत लागत धीरे-धीरे गिरकर 260 से 310 प्रति किलोग्राम के बीच आ सकती है, यानी लगभग 3 से 3.75 डॉलर प्रति किलोग्राम।

भारत हाइड्रोजन निर्माताओं को सस्ती अक्षय बिजली प्रदान करते आ रहा है, ओपन एक्सेस के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क माफ किया है और वितरण और ट्रांसमिशन शुल्क कम किया गया है। साथ ही, हाइड्रोजन के लिए जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इलेक्ट्रोलाइजर निर्माताओं के कुल सिस्टम लागत में 7 से 10 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा उपकरण है जो बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही हरित हाइड्रोजन योजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन दीर्घकालिक निवेश और परियोजना को बढ़ावा देने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है। इसमें कहा गया कि भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन को उद्योग जगत ने उत्साह के साथ अपनाया है। हालांकि, इस क्षेत्र में स्टार्टअप को आकर्षित करने और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाने और मांग को सुरक्षित करने की योजना को बेहतर बनाना होगा। अगर यह सफल रहा, तो यह कृषि, परिवहन और विनिर्माण सहित कई क्षेत्रों के लिए लाभ पहुंचाएगा। साथ ही, भारत के हरित हाइड्रोजन उद्योग को बनाने में मदद कर सकता है।

### सरकार की नीतियों से लागत में बड़ी गिरावट की संभावना

### 20 रुपए से कम का शेयर बना रॉकेट, निवेशकों पर बरसा रहा पैसा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** रतनइंडिया पावर लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी जारी है। बुधवार को बाजार खुलने के महज आधे घंटे के भीतर शेयर ने एक बार फिर जोरदार उछाल दर्ज किया। इससे पहले मंगलवार को भी यह स्टॉक करीब 18 प्रतिशत तक चढ़ा था। 20 रुपए से कम कीमत वाला यह स्टॉक इस सप्ताह अब तक 40 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, जिससे निवेशक और विश्लेषक दोनों ही हैरान हैं। बुधवार सुबह शेयर ने तेजी के साथ शुरुआत की और 12.70 प्रतिशत की उछाल के साथ 16.14 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि मंगलवार को यह 14.32 पर बंद हुआ था। हालांकि इसके बाद मामूली मुनाफावसूली देखी गई और सुबह 10 बजे यह शेयर करीब 10.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15.78 पर ट्रेड कर रहा था। इस शेयर में इस हफ्ते यानी सोमवार से लेकर अब तक जबरदस्त तेजी आई है। शुक्रवार को यह 11.19 रुपए पर बंद हुआ था। आज यानी बुधवार को यह अधिकतम 16.14 रुपए पर पहुंच गया।

## 1 जुलाई से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे तत्काल टिकट, रेल मंत्रालय का बयान

**नई दिल्ली, एजेंसी।** 10 जून, 2025 के एक परिपत्र में मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों को सूचित किया कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि तत्काल योजना का लाभ आम अंतिम उपयोगकर्ताओं को मिले। इसके तहत अब केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुक करवा सकेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि एक जुलाई 2025 के बाद से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल योजना के तहत टिकट बुक कर सकेंगे। 10 जून, 2025 के एक परिपत्र में मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों को सूचित किया कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि तत्काल योजना का लाभ आम अंतिम उपयोगकर्ताओं को मिले। मंत्रालय ने कहा, 01-07-2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे। इसके बाद, 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।

## सरकार ने लिया ऐसा फैसला, स्वदेशी शराब वाले स्टॉक 18% तक उछले

### विदेशी लिकर से जुड़े शेयर बुरी तरह गिरे

नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से शराब कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल, राज्य सरकार ने भारत में निर्मित विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है। इस वजह से शराब कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। हालांकि, कुछ शराब बनाने वाली कंपनियों के

शेयर तेजी से चढ़े हैं।

आज बाजार खुलने के बाद यूनाइटेड ब्रुवरीज, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, रेडिको खेतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी प्रमुख शराब कंपनियों के शेयरों में 5 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई। वहीं, सुला वाइनयार्डर्स, जीएम ब्रेवरीज और सोम डिस्टलरीज के शेयरों में 11 प्रतिशत तक की तेजी आई है।

यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयरों में 7.75न्न, एलाइड ब्लेंडर्स में 3.24न्न, तिलकनगर इंडस्ट्री में 2न्न और रेडिको खेतान में 1.90न्न की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है।

वहीं, सुला वाइनयार्डर्स के शेयर 8न्न, सोम डिस्टिलरीज के शेयर 3.25न्न और जीएम ब्रेवरीज के शेयर 18 न्न की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।

सुला वाइनयार्डर्स समेत अन्य शराब कंपनियों के शेयरों में तेजी के पीछे का कारण यह है कि निवेशकों को उम्मीद है कि महाराष्ट्र स्थित इन कंपनियों को नई पॉलिसी से महाराष्ट्र निर्मित शराब कैटेगरी से फायदा मिलेगा।

दरअसल, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा मंजूर नई दरों के तहत, आईएमएफएल पर एक्साइज ड्यूटी विनिर्माण लागत के तीन गुना से बढ़कर 4.5 गुना हो जाएगा, जबकि देसी शराब पर यह शुल्क 180 रुपये से बढ़कर 205 रुपये प्रति प्रूफ लीटर हो जाएगा। सरकार के इस कदम से सालाना 14,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

## सेंसेक्स 82,515 और निफ्टी 25,140 के पार बंद

**नई दिल्ली, एजेंसी।** बुधवार (11 जून) को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 123 अंक की तेजी के साथ 82,515 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी में 37 अंक की तेजी रही, ये 25,141 के स्तर पर क्लोज हुआ।

इससे पहले सेंसेक्स में 310 अंक से ज्यादा की तेजी रही, ये 82,712 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी में भी करीब 102 अंक की

तेजी रही, ये 25,206 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 38,385 पर और कोरिया का कोस्पी 0.66 प्रतिशत चढ़कर 2,890 पर कारोबार कर रहा है। हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.84न्न गिरावट के साथ 24,366 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.53 प्रतिशत गिरकर 3,402 पर कारोबार कर रहा है। 10 जून को अमेरिका का डाउ जोन्स 0.25 प्रतिशत बढ़कर 42,866 पर बंद हुआ। वहीं नैस्डेक कंपोजिट 0.63 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ।

**सरकार चलाएगी अभियान**

# बैंकों में जमा हजारों करोड़ रुपए लौटाने की तैयारी

**नई दिल्ली, एजेंसी।** देश के बैंकों में हजारों करोड़ रुपए वर्षों से लावारिस पड़े हैं, जिन पर किसी ने अब तक दावा नहीं किया है। अब केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर होती दिख रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वित्तीय नियामकों और संबंधित विभागों को इन जमाओं के असली मालिकों की पहचान कर राशि लौटाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सही दावेदारों तक इन जमाओं को पहुंचाने और केवाईसी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके लिए सभी नियामकों को जिला स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने को कहा गया है।

सीतारमण ने कहा कि जिला स्तर पर विशेष शिविरों के जरिए इस राशि को सही मालिकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यह अभियान भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, बीमा नियामक, पेंशन नियामक, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाएगा।

दावा न किए गए फंड्स में सिर्फ बैंकों की जमा राशि ही नहीं, बल्कि शेयर,

लाभांश, बीमा और पेंशन कोष की भी बड़ी हिस्सेदारी है।

आरबीआई की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2024 के अंत तक बैंकों में दावा न की गई जमा राशि 26 फीसदी बढ़कर 78,213 करोड़ रुपए हो गई थी। यह रकम वर्षों से निष्क्रिय खातों, मृतक खाताधारकों की राशि या अधूरी केवाईसी प्रक्रियाओं के कारण अटकी हुई है। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के लिए भी डिजिटल केवाईसी सुविधा को आसान बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में केवाईसी को लेकर एक समान मानदंड और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

यह चर्चा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री सीतारमण ने की। बैठक में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे, वित्त सचिव अजय सेठ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

# एक अगस्त से यूपीआई के नियमों में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। यूपीआई के नियमों में 1 अगस्त से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो देश के डिजिटल भुगतान सिस्टम की मजबूती और स्थिरता के लिए जरूरी हैं। यूपीआई पर हो रहे बढ़ते ट्रांजैक्शन के दबाव को कम करने और सिस्टम की गति बनाये रखने के लिए नई पाबंदियां और उनका आपके डिजिटल लेनदेन पर क्या असर होगा।

देश में यूपीआई से हो रहे भारी ट्रांजैक्शन की वजह से सिस्टम पर लोड काफी बढ़ गया है। तकनीकी नियमों में बदलाव का उद्देश्य गैरजरूरी और बार-बार आने वाली एपीआई रिक्वेस्ट को

लागू की जा रही हैं। खासतौर पर बैंक बैलेंस चेकिंग, बैंक खातों की जानकारी देखने और ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन पेमेंट पर सीमाएं लगाई जाएंगी। आइए जानते हैं इन बदलावों की पूरी जानकारी

कंट्रोल करना है ताकि यूपीआई सिस्टम की स्थिरता बनी रहे और यह तेजी से काम करता रहे।

अब आप दिन भर में केवल 50 बार अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस यूपीआई ऐप के जरिए देख पाएंगे। इससे अत्यधिक बार बार बैलेंस चेक करने वाले उपयोगकर्ताओं पर कंट्रोल होगा।

अगर आपके मोबाइल नंबर से कई बैंक अकाउंट लिंक हैं, तो आप इन खातों की जानकारी एक दिन में सिर्फ 25 बार देख पाएंगे। इससे डेटा की अधिकता और सिस्टम पर अनावश्यक भार कम होगा।

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, एसआईपी जैसी सेवाओं के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट अब केवल नॉन पीक ऑवर्स में ही किए जा सकेंगे।

यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को आम जनता तक पहुंचा दिया है। बिना बैंक डिटेल्स के, सिर्फ मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन करना अब आम बात हो गई है। लाखों छोटे व्यापारी, रिक्शा चालक और कंस्यूमर इससे जुड़े हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपीआई सिस्टम के लगातार बढ़ते उपयोग को देखते हुए यह कदम जरूरी था ताकि प्लेटफॉर्म सुचारू रूप से काम करता रहे। नए नियमों से तकनीकी सुधार होगा, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस पर भी खास ध्यान रखा गया है ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो।

## भारतीय शेयर बाजार का जलवा, अमेरिका-चीन को पछाड़ा, बना दुनिया का टॉप ग्रोइंग शेयर मॉर्केट

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। मार्च 2025 की शुरुआत से अब तक भारत में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण करीब 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़कर 5.33 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 21 प्रतिशत की यह वृद्धि दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजारों में सबसे तेज़ है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज बाजारों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता शेयर बाजार बनने का गौरव हासिल किया है। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद वैश्विक स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा बाजार है। वैश्विक स्तर पर भारत के बाद जर्मनी के बाजार ने दूसरा सबसे बड़ा लाभ दर्ज किया, जिसका एमकैप इस अवधि के दौरान लगभग 14 प्रतिशत बढ़ा। कनाडा में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि हांगकांग में 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई। जापान और यूनाइटेड किंगडम में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी बाजार है, ने लगभग 2.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की, जबकि दूसरे सबसे बड़े चीन में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। फ्रांस और ताइवान ने क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की। मार्च महीने से लेकर अबतक भारत के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी में 12.5 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 20.7 प्रतिशत और 26 प्रतिशत से अधिक चढ़े हैं। भारतीय शेयर बाजार में रैली लौटने से निवेशकों की बंपर कमाई हुई है। इससे निवेशक एक बार फिर गदगद हैं।

### ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार से जुड़ी नीतियों को बेहतर बनाने पर हो रही चर्चा : पीयूष गोयल

**नई दिल्ली, एजेंसी।** केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खुदरा व्यापार नीति पर भी चर्चा चल रही है क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड से राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति तैयार करने के लिए सुझाव देने को कहा है। प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार नीतियों पर चर्चा चल रही है क्योंकि दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। विभिन्न देशों के साथ व्यापार वार्ता के लिए विदेश दौरे पर गए वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि चूंकि ई-कॉमर्स क्षेत्र एक उभरता हुआ और तेजी से बदलता हुआ विषय है, इसलिए हमने कुछ विचार सामने रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे और अधिक समसामयिक बनाने के लिए हमें नीति में संशोधन करना होगा और इस पर चर्चा चल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खुदरा व्यापार नीति पर भी चर्चा चल रही है क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड से राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति तैयार करने के लिए सुझाव देने को कहा है। वर्ष 2021 में खुदरा व्यापार को सुव्यवस्थित करने और खुदरा व्यापार क्षेत्र के सभी स्वरूपों के सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकास के लिए खुदरा व्यापार नीति का मसौदा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, किफायती ऋण तक आसान और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना व खुदरा व्यापार के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाना है। इससे पहले, मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीतियों के दो प्रारूप जारी किए हैं। 2019 के मसौदे में ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र के छह व्यापक क्षेत्रों- डेटा, बुनियादी ढांचे का विकास, ई-कॉमर्स बाजार, नियामकीय मुद्दे, घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना और ई-कॉमर्स के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देने का प्रस्ताव किया गया है।

# रिकॉर्ड ऊंचाई पर चांदी के दाम, इस लेवल तक जाएगी कीमत

**नई दिल्ली, एजेंसी।** लगातार बढ़ रही चांदी की कीमतों ने सबको चौंका दिया। फिलहाल चांदी का भाव प्रति किलो 1 लाख से ऊपर चल रहा है और बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिवाली तक यह 1.30 लाख प्रति किलो के पार पहुंच सकता है। यह तेजी सिर्फ आम ग्राहकों ही नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय सुरेश केडिया के मुताबिक, वैश्विक बाजार में तकनीकी ब्रेकआउट के चलते चांदी की कीमत में यह उछाल देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में चांदी का भाव 1.25 लाख से 1.30 लाख प्रति किलो के बीच पहुंच सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव 37 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया है, जो एक महत्वपूर्ण स्तर माना जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में कुछ नरमी आने से भी औद्योगिक मांग में तेजी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की मांग इलेक्ट्रिक वाहनों, 5न्न तकनीक और क्लीन एनर्जी सेक्टर में सबसे अधिक है, जिससे इसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत 1,000 की तेजी के साथ 1,08,100 प्रति किलोग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वहीं, सोना 110 गिरकर 97,670 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ज्वेलर्स और स्टॉकिस्टों द्वारा की जा रही बिकवाली की वजह से सोने में यह गिरावट देखी गई।

# एनसीएलटी ने आईनॉक्स विंड एनर्जी व आईनॉक्स विंड के विलय को मंजूरी दी

**नई दिल्ली, एजेंसी।** आईनॉक्सजीएफएल समूह ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मंगलवार को एनसीएलटी के आदेश के बाद आईनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का आईनॉक्स विंड लिमिटेड (आईडब्ल्यूएल) में विलय हो जाएगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की चंडीगढ़ पीठ ने आईनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड और आईनॉक्स विंड लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से आईनॉक्सजीएफएल समूह के पवन व्यवसाय को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा और समग्र परिचालन क्षमता में सुधार होगा।

आईनॉक्सजीएफएल समूह ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मंगलवार को एनसीएलटी के आदेश के बाद आईनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का आईनॉक्स विंड लिमिटेड (आईडब्ल्यूएल) में विलय हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस विलय से आईनॉक्सजीएफएल समूह के पवन ऊर्जा व्यवसाय का सरलीकरण और सुव्यवस्थितीकरण होगा, तथा समग्र परिचालन क्षमता में सुधार होगा।

## देश तरक्की करता हैं... तब कांग्रेस पार्टी को दुख होता : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष कर कहा कि उनके पास कांग्रेस के लिए कोई इलाज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी देश आगे बढ़ता है, तब कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ नेता दुख में डूब जाते है।भाजपा सांसद ने बीते 11 वर्षों में भारत के विकास पर कहा कि भारत का निर्यात 50 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 800 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते 11 साल में इतना काम हुआ है कि योजनाओं के नाम गिनना मुश्किल है। हम सभी पहलुओं में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और निर्यात भी तेजी से बढ़ा है और 800 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। जब मैं नया मंत्री था, तब हम करीब हर चीज का आयात कर रहे थे। हमारा निर्यात 50 अरब डॉलर भी नहीं था। अगर कांग्रेस दुखी होती है जब देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की जनता खुश है, तब मेरे पास उनके लिए कोई इलाज नहीं है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि लोक संवर्धन पर्व एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि गांवों में जो कौशल है उनके उत्पादों को बाजार में लाने, उन्हें एक मंच देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इससे विभिन्न राज्यों के उत्पादों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

## सुवेंदु अधिकारी की ममता सरकार से मांग, पीड़ितों से मिलने दिया जाए

कोलकाता (एजेंसी)। विवादित भूमि को लेकर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प के बाद दक्षिण 24 परगना के रवींद्रनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कथित तौर पर महेशतला (मेटियाबुज विधानसभा क्षेत्र के तहत) के वार्ड नंबर 7 में अतिक्रमित भूमि पर दुकानें बनाने से शुरू हुआ विवाद तेजी से बढ़ गया। इस दौरान पत्थर और ईंटें फेंकी गईं और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। दक्षिण 24 परगना में उपद्रवियों और पुलिस के बीच झड़प पर एलओपी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले के आदेश में खास तौर पर कहा था कि जहां भी सांप्रदायिक हिंसा होगी, लोगों को लूटा जाएगा, पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जाएगा और वे घायल होते हैं, तब याचिकाकर्ता डीजीपी को मेल भेजेगा और इसके तहत मैंने कल ऐसा किया। मैंने डीजीपी से मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल सका। कुछ अधिकारियों ने मुझे बताया है कि उन्होंने (डीजीपी) ममता बनर्जी से बात की, और उन्होंने कहा कि उनसे (सुवेंदु अधिकारी से) मिलने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा नेता का दावा हैं कि उसी आदेश में यह भी लिखा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तब कोर्ट केंद्रीय अर्धसैनिक बल को निर्देश देगा, यह आदेश 30 जुलाई तक वैध है। इसलिए हम इसी मांग को लेकर याचिका दायर कर रहे हैं। हमारे द्वारा इसके लिए दो स्थगन प्रस्ताव भी दिए हैं... मैंने डीजीपी और एसपी डायमंड हार्बर को पहले ही ईमेल भेज दिया है कि एलओपी और एक विधायक को पीड़ितों से मिलने की अनुमति दी जाए।

## तीन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 19 लाख रुपये का था इनाम

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 19 लाख रुपये के इनामी तीन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अनुसार, यह घटनाक्रम सुकमा जिले में 16 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है। इसमें छह नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 25 लाख रुपये का इनाम था। इसमें से नौ नक्सली केरलापेंडा ग्राम पंचायत के थे। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व बस्तर डिवीजन में कंपनी नंबर छह में सक्रिय नक्सली भीमा उर्फ ढोलू उर्फ दिनेश पोड़ियाम (40) ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित है। उन्होंने बताया कि इसके पहले जिले में दो महिला नक्सली सुकली कोर्राम उर्फ सपना और देवली मंडावी ने भी आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि सुकली पर आठ लाख तथा देवली पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने पर नक्सलियों को 50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया है तथा उन्हें नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में इस वर्ष कुल 104 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया है।

## यूपी में हीटस्ट्रोक से 5 की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपी भीषण लू की चपेट में है। पिछले 24 घंटे में हीटस्ट्रोक से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर में गर्मी से 12 बगुलों की मौत हो गई। मोतीझील किनारे दीवारों पर बगुले मृत पाए गए।

इधर, उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। 15 जून को प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। अनिल ने कहा- इस समय गर्मी ज्यादा है, बच्चे बीमार हो सकते हैं।

# ईरान और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर अमेरिका की नजर, करेगा बड़ा खेला

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** ईरान और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर अमेरिका की चिंता एक जटिल जियो-पॉलिटिकल परिदृश्य का हिस्सा बनी हुई है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करता है। यह चिंता न केवल इन देशों की परमाणु क्षमताओं से, बल्कि इनके रणनीतिक संबंधों और क्षेत्रीय प्रभाव से भी जुड़ी है।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता का कारण है। 2015 में ईरान और अमेरिका ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए, इसके तहत ईरान ने अपने परमाणु गतिविधियों में कटौती करने और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार करने का वादा किया था, बदले में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली।

हालांकि, 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया, जिससे तनाव बढ़ गया। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाया है, जो 2015 की सीमा से 22 गुना ज्यादा है।

अक्टूबर 2023 की आईएईए रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अपने यूरेनियम संवृद्धि को बढ़ाया है, जिससे चिंताएं बढ़ी हैं कि वह परमाणु हथियार बनाने को तैयार है। अमेरिका को डर है कि एक परमाणु-सशस्त्र ईरान मध्य पूर्व में अस्थिरता ला सकता है। उसके सहयोगियों जैसे इजराइल और सऊदी अरब को खतरा पैदा कर सकता है।

इसके लिए अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है, खासकर अगर वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सैन्यीकरण को लेकर चिंताओं को संबोधित करती है। हालांकि, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा है कि वे अमेरिका के धमकी के तहत बातचीत नहीं करने वाले हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। वहीं पाकिस्तान पहले से ही परमाणु हथियारों से लैस है। इसका परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए चिंता का विषय रहा है। खासकर भारत के साथ क्षेत्रीय तनाव के बाद में। हाल ही में, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाइयों ने परमाणु संघर्ष के जोखिम को उजागर किया है, जिससे अमेरिका को मध्यस्थता करनी पड़ी।

मई 2025 में दोनों देशों ने एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले किए, जिससे गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। पाकिस्तान का चीन के साथ परमाणु सहयोग भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं को मजबूत करने में मदद की है। पाकिस्तान का ड्रैगन के साथ सहयोग दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जो अमेरिका के रणनीतिक हितों के लिए ठीक नहीं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में हुई थी, जब अमेरिका ने पता लगाया कि पाकिस्तान गुप्त रूप से यूरेनियम संवृद्धि कर रहा है। पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए। अब उसके पास लगभग 165 परमाणु वारहेड्स हैं, जो भारत और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करते हैं।

अमेरिकी चिंता का एक बड़ा हिस्सा यह है कि ईरान और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। एक परमाणु-सशस्त्र ईरान मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन के लिए खतरा है, जबकि पाकिस्तान के मामले में, भारत के साथ तनाव और चीन के साथ सहयोग एक जटिल रणनीति पैदा करते हैं।

## शेख हसीना का बड़ा दावा, अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी सौंप देती...तब सत्ता में होती

**नई दिल्ली।** बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस को आतंकियों का समर्थन कर देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। हसीना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यूनुस के शासन में देश में अपराध और हिंसा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं शहरों में सुरक्षित महसूस नहीं करतीं और त्यौहारों पर लोग गांव जाने से डरते हैं, क्योंकि आतंकियों का डर बना रहता है। शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि यूनुस 2026 में चुनाव कराने की बात कहकर बांग्लादेश की जनता के साथ अप्रैल फूल बना रहे हैं। हसीना ने कहा कि यूनुस संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के एक पुराने सुझाव को लेकर रोहिंग्या कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप बेचा जा सकता है और समुद्र तक देश की पहुंच खतरे में पड़ सकती है। हसीना ने चेतावनी दी कि यह कॉरिडोर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है और विदेशी ताकतें इसका फायदा उठा सकती हैं। सेना प्रमुख ने भी खूनी कॉरिडोर बताकर कहा था कि इस पर कोई फैसला केवल चुनी हुई सरकार ही ले सकती है। हसीना ने दावा किया कि अगर वह अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी सौंप देतीं, तब आज भी सत्ता में होतीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह देश की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकतीं।

## कर्नाटक-कैबिनेट ने नए सिरे से जाति सर्वेक्षण कराने का किया फैसला, 90 दिनों में होगा पूरा

**बेंगलुरु (एजेंसी)।** बेंगलुरु में गुरुवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व की इच्छा के अनुसार राज्य भर में एक नया सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने और इसे 90 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कानून के अनुसार इस तरह के सर्वेक्षण के निष्कर्ष केवल 10 साल के लिए वैध हैं। कर्नाटक का सर्वेक्षण केंद्र की जाति जनगणना से किस तरह अलग होगा, इस सवाल पर सीएम ने कहा कि केंद्र ने यह नहीं कहा है कि वह सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र में पार्टी द्वारा किए गए वादे के अनुसार सामाजिक न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पूर्व महाधिवक्ता मधुसूदन नाइक की अध्यक्षता वाले कर्नाटक राज्य स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग से 90 दिनों में सर्वेक्षण रिपोर्ट देने को कहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने यह काम 70 दिनों में पूरा कर लिया। गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जब एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से जातियों की फिर से गणना करने को कहा। यह कर्नाटक के प्रमुख समुदायों की शिकायतों का जवाब था कि सर्वेक्षण के लिए एकत्र किए गए डेटा में जाति की फिर से गणना की गई है। इससे पहले सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि जाति जनगणना के आंकड़ों को फिर से दर्ज करने का फैसला पार्टी हाईकमान ने लिया है और यह राज्य सरकार का फैसला नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं।

# 2030 तक देश के बड़े शहरों में बढ़ेगी गर्मी और बारिश मचाएगी तबाही

### – अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा, जलवायु परिवर्तन से बिगड़ रहे हालात

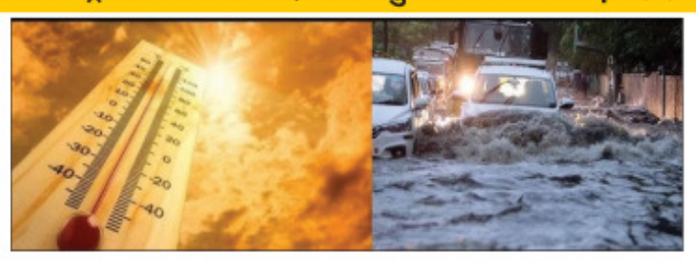

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** 2030 तक देश के कई बड़े शहरों में गर्मी और बारिश का कहर और बढ़ जाएगा। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली समेत मुंबई, चेन्नई, सूरत, ठाणे, हैदराबाद, पटना और भुवनेश्वर में अगले कुछ सालों में भीषण हीटवेव का खतरा दोगुना हो जाएगा यानी अब गर्मी केवल मई-जून तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मानसून के दौरान भी लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट 'तूफान का सामना करना, गर्म होते जलवायु में मानसून का प्रबंधन नाम से आई है, जिसे दो समूह ने मिलकर जारी की है। रिपोर्ट को जलवायु विशेषज्ञों ने तैयार किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबे समय तक चलने वाली गर्म हवाओं के कारण न सिर्फ लू का खतरा बढ़ेगा, बल्कि बारिश भी अनियमित हो जाएगी। भारत के करीब 80 फीसदी जिलों में 2030 तक मानसून के दौरान भारी बारिश और हीटवेव दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में तो इस साल मई-जून में कई बार लू चली है।

रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में मानसून के मौसम में भी तापमान सामान्य से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी और भारी बारिश की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अब ये हालात केवल गर्मियों तक सीमित नहीं रहेंगे। मानसून के दौरान भी तापमान में खतरनाक बढ़ोतरी हो रही है। इससे लगातार तेज गर्मी और मूसलाधार बारिश का मेल तैयार हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक देशभर में हीटवेव के दिनों में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा अत्यधिक बारिश की घटनाओं में 43 फीसदी तक इजाफा हो सकता है यानी एक तरफ तेज गर्मी तो दूसरी ओर अचानक तेज बारिश। दोनों ही हालात जलवायु परिवर्तन की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। विश्लेषण में ये भी बताया गया है कि पिछले 30 सालों में मार्च से सितंबर तक हीटवेव वाले दिनों में 15 गुना तक बढ़ोतरी हुई। सिर्फ पिछले 10 सालों में ही ऐसी घटनाएं 19 गुना बढ़ी हैं। इससे साफ होता है कि अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और हमें इन खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

दिल्ली समेत देश के 72 फीसदी टियर-1 और टियर-2 शहरों में गर्मी और बारिश के इन खतरों के साथ-साथ तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि जैसी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में खतरा ज्यादा रहेगा। गुजरात, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के करीब 75 फीसदी जिलों को अगले पांच साल में लगातार गर्मी और अनियमित बारिश का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी इलाके अब जलवायु परिवर्तन के सबसे संवेदनशील हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं।

रिपोर्ट में आगे ये सुझाव भी दिया गया कि देश में जलवायु जोखिम को समझने के लिए एक 'क्लाइमेट रिस्क ऑब्जर्वेटरी' यानी जलवायु जोखिम वेधशाला बनाई जानी चाहिए। इससे हर इलाके का बारीकी से आकलन किया जा सकेगा और समय रहते अलर्ट जारी किए जा सकेंगे साथ ही सरकार को ऐसे आर्थिक उपाय भी करने होंगे जिससे आम लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक असर को संभाला जा सके।

## अमेरिका ने भारत को दिए तीन कूटनीतिक झटके... लेकिन फिर भी मोदी चुप

### कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी सांसदों से मिलने की मांग की

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि एक ही दिन में भारत की कूटनीति को अमेरिका से तीन बड़े झटके लगे हैं। इससे भारतीय विदेश नीति और भारत-अमेरिका संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कांग्रेस नेता जयराम ने कहा कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बताया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिकी आर्मी डे के लिए न्यौता दिया है। वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि भारत-पाक तनाव ट्रंप ने खत्म कराया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये हमारी कूटनीति के लिए बड़े झटके हैं। प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं, उन्हें अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने विदेश यात्राओं पर गए सांसदों से मुलाकात की है, अब विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलना चाहिए। मोदी सरकार पर हमलावार कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ जनरल कुरिल्ला ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पाकिस्तान को एक शानदार साझेदार बताया। क्या यहीं पाकिस्तान है जहां ओसामा बिन लादेन 10 साल छिपा रहा और 2011 में मारा गया। वहीं पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए आतंकवाद विरोधी साझेदार बन गया।

कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर को अमेरिका सेना की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में भाग लेने के लिए न्यौता भेजा है। यह वहीं मुनीर है, जो कि पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले भड़काऊ और उकसावे बयान दिए थे। उनके बयानों से ही आतंकियों को बल मिला। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने फिर कहा कि भारत-पाक तनाव को कम करने में डोनाल्ड ट्रम्प और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भूमिका रही है।

## फडणवीस और राज ठाकरे की गुपचुप मुलाकात... क्या उद्धव से बिगड़ गई बात

**मुंबई (एजेंसी)।** महाराष्ट्र की राजनीति में गुरुवार को एक बड़ा घटनाक्रम दिखाई दिया, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुंबई के पांच सितारा होटल में बंद कमरे में बैठक हुई। यह मुलाकात करीब एक घंटे चली और बैठक को किसी भी पक्ष ने पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। यह मुलाकात तब हुई है जब शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) लगातार एमएनएस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को हवा दे रही थी और 'मराठी मानूस' की एकजुटता की अपील हो रही थी। वहीं, एमएनएस की चुप्पी और अब भाजपा नेताओं से मुलाकात इस बात का संकेत देती है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बजाय भाजपा और शिंदे गुट के साथ जुड़ने का मन बना रहे हैं।

बता दें कि 14 जून को राज ठाकरे और 13 जून को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन है। शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ता इन तारीखों को प्रतीकात्मक एकता दिवस के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन यह अचानक बैठक उनके मंसूबों पर पानी फेर सकती है।

पिछले कुछ महीनों से उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य और संजय राऊत सहित शिवसेना (यूबीटी) के नेता लगातार राज ठाकरे से सार्वजनिक अपील कर रहे थे। पुराने पारिवारिक फोटो, सोशल मीडिया पोस्ट और सामना में प्रकाशित भावनात्मक लेखों के माध्यम से मराठी अस्मिता की एकता का संदेश दिया जा रहा था। लेकिन एमएनएस की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई।

वहीं राज ठाकरे को भाजपा के अलावा शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से भी गठबंधन का प्रस्ताव मिला है। संजय शिरसाट, मंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता ने कहा, ÷हमने पहले भी विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन की पेशकश की थी। आज भी हम राज साहेब को साथ आने का निमंत्रण देते हैं।÷

# यूएन की रिपोर्ट: भारत में घट रही प्रजनन दर, भविष्य के लिए चुनौती

### -बढ़ती बुजुर्ग आबादी और घटती युवा शक्ति के लिए ठोस नीति जरुरी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारत की जनसंख्या में बड़ा और निर्णायक बदलाव आया है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट 2025 के मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर अब 'प्रत्यास्थापन स्तर' यानी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली गई है। इसका मतलब है कि अब जितने लोगों की देश में मौत हो रही है, उतने नए जन्म नहीं ले हो रहे। 2025 के अंत तक भारत की जनसंख्या के 1.46 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, जबकि स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए यह दर कम से कम 2.1 होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने इसे एक 'वास्तविक प्रजनन संकट' करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने इच्छित परिवार आकार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो कुछ सामाजिक, आर्थिक या स्वास्थ्य कारणों से बच्चे पैदा करने का फैसला टाल रहे हैं। गर्भनिरोधक साधनों की सीमित पहुंच, करियर व शिक्षा की प्राथमिकता, बदलती जीवनशैली और सामाजिक धारणाएं इस बदलाव के मुख्य कारण माने जा रहे हैं।

भारत में हालांकि अभी युवा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मौजूद है।

रिपोर्ट के मुताबिक देश की जनसंख्या में 0 से 14 साल के लोग 24फीसदी, 10 से 19 वर्ष के 17 फीसदी, 10 से 24 वर्ष के 26फीसदी और 15 से 64 वर्ष के लोग 68फीसदी हैं। इसका अर्थ है कि भारत फिलहाल एक बड़े 'जनसांख्यिकीय लाभांश' की स्थिति में है। यदि सरकार इस युवा शक्ति को सही दिशा दे सके, तो देश अगले कुछ दशकों में वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सकता है।

यूएन रिपोर्ट यह बताती है कि भारत अब मध्यम आय वाले उन देशों की श्रेणी में आता है, जहां जनसंख्या दोगुनी होने में करीब 79 साल लगेंगे। यह एक अहम बदलाव है, क्योंकि पहले यह समय कहीं कम था। यूएनएफपीए की भारत में प्रतिनिधि के मुताबिक भारत ने बीते 50 सालों में प्रजनन दर कम करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1970 में जहां एक महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म देती थी, अब यह संख्या करीब 2 हो चुकी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार का परिणाम है।

विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यह गिरावट इसी तरह जारी रही तो आने वाले सालों में भारत को तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और घटती युवा शक्ति के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी। यह बदलाव भविष्य की सामाजिक संरचना और आर्थिक उत्पादकता दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717